पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः पौष 01, 1944
वीरवारः 22 दिसंबर 2022

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 84,328 करोड़ रुपये के 24 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दी

इनमें से 82,127 करोड़ रुपये मूल्य के 21 प्रस्तावों को स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए मंजूरी दी

प्रस्तावों में फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, लाइट टैंक्स, नौसेना पोत रोधी मिसाइल, बहुउद्देश्यीय जलयान, मिसाइल प्रणाली की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशित बम और अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत शामिल हैं

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 22 दिसम्बर 2022 को बैठक में 24 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों में 84,328 करोड़ रुपये के भारतीय थल सेना के लिए छह, भारतीय वायु सेना के लिए छह, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो प्रस्ताव शामिल हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए 82,127 करोड़ रुपये (97.4%) के 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की यह अभूतपूर्व पहल न केवल सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए रक्षा उद्योग को भी पर्याप्त बढ़ावा देगी।

अनुमोदित आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) भारतीय सेना को भविष्य के इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, लाइट टैंक्स और माउंटेड गन सिस्टम जैसे प्लेटफार्मों और उपकरणों से लैस करेगी, जिससे भारतीय सेना की संक्रियात्मक तैयारियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अनुमोदित प्रस्तावों में हमारे सैनिकों के लिए बढ़े हुए सुरक्षा स्तर के साथ बैलिस्टिक हेलमेट की खरीद भी शामिल है।

नौसेना पोत-रोधी मिसाइल, बहुउद्देश्यीय जलयान और हाई इन्ड्योरेंस ऑटोनोम्स व्हीक्लस की खरीद के लिए अनुमोदन भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देते हुए समुद्री ताकत को और बढ़ाएगा।

भारतीय वायु सेना को मिसाइल प्रणाली की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशित बम, पारंपरिक बमों के लिए रेंज ऑग्मेंटेशन किट और उन्नत निगरानी प्रणालियों को शामिल करके बढ़ी हुई घातक क्षमताओं के साथ और मजबूत किया जाएगा।

भारतीय तटरक्षक बल के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों की खरीद से तटीय क्षेत्रों में निगरानी क्षमता नई ऊंचाइयों तक बढ़ेगी।

एबीबी/डीएस